Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

Original Article

आदिवासी महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थितिः एक मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य गोड्डा ज़िले के संदर्भ में

डॉ. कंचन
पी–एच. डी. पंजीयन संख्या–7340 / 2017, स्नातकोत्तर मानवशास्त्र विभाग, ति. माँ. भा. वि. वि., भागलपुर
Email: malakanchan3112@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2025-170767
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 7|
Pp. 338-347
July 2025
Submitted: 21 June. 2025
Revised: 31 June. 2025
Accepted: 16 July. 2025
Published: 31 July. 2025

सारांश

अध्ययन "आदिवासी महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थितिः एक मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, गोड्डा ज़िले के संदर्भ में" विषय पर केंद्रित है, जिसमें गोड्डा ज़िले की आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर, शिक्षा में भागीदारी, सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ, लिंग आधारित भूमिका तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य यह है कि आदिवासी समुदाय की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने में कौन–कौन सी चुनौतियाँ आती है, जैसे पारिवारिक आर्थिक स्थिति, विवाह की पारंपरिक प्रथाएँ, सांस्कृतिक प्रतिबंध, विद्यालयों की भौगोलिक दूरी आदि। इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि शिक्षा कैसे उनके जीवन में सामाजिक परिवर्तन, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती है। शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से डेटा एकत्र कर विश्लेषण किया गया है। अंततः अध्ययन के आंकड़ों के आधार पर नीतिगत प्रयास, जमीनी हकीकत के अनुरूप है या नहीं की जांच की गई है। समुदाय में शिक्षा एवं योजना के प्रति जागरूकता में वृद्धि होने से आदिवासी महिलाओं की शिक्षा में ठोस सुधार संभव हुआ है। शोध न केवल आंकड़ों का विवेचन करता है, बल्कि स्थानीय जीवन–शैली और संस्कृति के मध्य शिक्षा की संभावनाओं को भी उजागर करता है।

शब्द–कुंजी– *व्यक्तिगत सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक समूहों, संरचनात्मक पहलु विकासीय संकेतक, सांस्कृतिक असंगति, मानव विकास सूचकांक, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, संस्थागत प्रथाओं, नृवंशविज्ञानी, दुर्गमता, सउद्देश्यपूर्ण निदर्शन, सांस्कृतिक असंबद्धता, अनौपचारिक प्रशिक्षुता।*

प्रस्तावना

शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत सशक्तिकरण और आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। भारत में शिक्षा का लाभ सभी सामाजिक–सांस्कृतिक समूहों में समान रूप से वितरित नहीं हुआ है। आदिवासी महिलाएँ सबसे अधिक वंचित वर्गों में से एक है, जो न केवल स्वदेशी समुदायों की सदस्य होने के कारण हाशिए पर है, बल्कि एक मजबूत पितृसत्तात्मक समाज में महिला होने के कारण भी दोहरी उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। लिंग, जातीयता और गरीबी के बीच अंतःसंबंध के कारण, आदिवासी महिलाएं शिक्षा तक पहुँच और उपलब्धि के मामले में विशेष रूप से कमजोर स्थिति में है। झारखंड के गोड्डा ज़िले में आदिवासी महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थिति की व्यापक समझ हेतु अध्ययन किया गया है। गोड्डा पूर्वी भारत का एक अत्यंत पिछड़ा और जनजातीय–प्रधान ज़िला है, इस जिले में संथाल, पहाड़िया और उरांव जैसी जनजातियाँ बड़ी संख्या में निवास करती है। अध्ययन की पद्धति मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित है, जिससे सांस्कृतिक, सामाजिक और संरचनात्मक पहलुओं की गहरी समझ प्राप्त हो सकती है।

मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से, शिक्षा केवल रोज़गार या आर्थिक गतिशीलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाजीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मूल्यों, सांस्कृतिक परंपराओं और विश्व दृष्टिकोण का संचरण होता है। आदिवासी समाजों में, जहाँ मौखिक परंपराएं, सामुदायिक जीवनशैली और प्रकृति–केंद्रित दृष्टिकोण प्रचलित है, वहीं मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली, जो प्रायः अंग्रेजी भाषाओं में और अमूर्त पाठ्यक्रमों पर आधारित होती है, उनके जीवन कटे हुए और अप्रासंगिक प्रतीत होते हैं। यह सांस्कृतिक असंगति (Cultural Dissonance) विद्यालय ड्रॉपआउट्स, खराब शैक्षिक प्रदर्शन और औपचारिक शिक्षा के प्रति प्रतिरोध की ओर ले जाती है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ. कंचन, पी-एच. डी. पंजीयन संख्या-7340/2017, स्नातकोत्तर मानवशास्त्र विभाग, ति. माँ. भा. वि. वि., भागलपुर

How to cite this article:
कंचन. (2025). आदिवासी महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थितिः एक मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य गोड्डा ज़िले के संदर्भ में. Journal of Research & Development, 17(7), 338–347.
https://doi.org/10.5281/zenodo.16931914

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI:10.5281/zenodo.16931914
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

अध्ययन के उद्देश्य

शोध का मुख्य उद्देश्य गोड्डा ज़िले की आदिवासी महिलाओं की वर्तमान शैक्षिक स्थिति का आकलन करना है, जिसमें साक्षरता स्तर, विद्यालय नामांकन और शैक्षणिक उपलब्धियों की पहचान की जाएगी। इन सतही मानकों के अतिरिक्त, अध्ययन का उद्देश्य उन अंतर्निहित सामाजिक–सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, सामुदायिक अपेक्षाओं, लैंगिक मानदंडों और संस्थागत प्रथाओं को समझना है, जो आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक भागीदारी को या तो बढ़ावा देता है या बाधित करता है।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है:

1. गोड्डा ज़िले की आदिवासी महिलाओं में शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर (साक्षरता, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा) का मूल्यांकन करना।
2. आदिवासी महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच और उसे बनाए रखने की क्षमता को सीमित करने वाले सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना।
3. आदिवासी महिलाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने हेतु सरकारी और गैर–सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
4. शिक्षा और आत्मविकास के संदर्भ में आदिवासी महिलाओं के जीवन अनुभवों, धारणाओं और आकांक्षाओं को समझना।
5. आदिवासी क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और लिंग–संवेदनशील शैक्षिक सुधारों को दिशा देने वाले मानवशास्त्रीय अंतर्दृष्टि और नीतिगत सिफ़ारिशें प्रदान करना।

अध्ययन के उद्देश्य न केवल आँकड़ों के संग्रहण बल्कि विश्लेषण प्रक्रिया को भी मार्गदर्शित करने के लिए निर्माण किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अध्ययन तथ्यात्मक साक्ष्य और सांस्कृतिक संदर्भ दोनों में दृढ़ता से स्थापित हो।

3. अनुसंधान पद्धति (Methodology)

अध्ययन के लिए अनुसंधान पद्धति के रूप में गुणात्मक–परिमाणात्मक दृष्टिकोण (Mixed-Methods Approach) पर आधारित है, जो सांख्यिकीय विश्लेषण के साथ–साथ नृवंशविज्ञानी व्याख्या की सुविधा भी प्रदान करता है। अध्ययन का उद्देश्य केवल साक्षरता स्तर को मापना नहीं है, बल्कि उन सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों को भी समझना है जो आदिवासी महिलाओं के शैक्षिक व्यवहार को प्रभावित करता है, इसलिए मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है।

अनुसंधान प्रचना (Research Design)

अध्ययन क्रॉस–सेक्शनल फील्ड सर्वे के रूप में प्रचित किया गया है, जो फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच झारखंड के गोड्डा ज़िले में संपन्न हुआ है। शोध का केंद्र तीन प्रमुख प्रखंडों पथरगामा, सुंदरपहाड़ी और बोआरीजोर था, जहाँ आदिवासी जनसंख्या सघन है। इन क्षेत्रों का चयन जनसांख्यिकीय संरचना, दुर्गमता और संथाल, पहाड़िया और उरांव जैसे विविध जनजातीय समुदायों की उपस्थिति के आधार पर किया गया है। अध्ययन में संरचित सर्वेक्षण के साथ–साथ गहराई से गुणात्मक तकनीकों जैसे कि सहभागी अवलोकन, प्रमुख सूचनादाताओं के साक्षात्कार और केंद्रित समूह चर्चा (FGDs) का प्रयोग किया गया है।

निदर्श आकार एवं निदर्श चयन तकनीक (Sample Size And Sampling Technique)

अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण निदर्श प्रणाली (Purposive Sampling) का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत 50 आदिवासी महिलाओं को उत्तरदाता के रूप में चुना गया है। "निदर्श का चयन आयु (15–40 वर्ष), शैक्षिक पृष्ठभूमि (अशिक्षित से स्नातक) और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर किया गया है। तकनीक उन प्रतिभागियों को शामिल करने की सुविधा देता है, जो अध्ययन के उद्देश्यों से सीधे जुड़े होते हैं।"[1]

झारखंड राज्य 2000 ई. में बिहार से अलग होकर बना था, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा को दूर करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इसके बावजूद, आदिवासी क्षेत्रों में विकासीय संकेतक अभी भी चिंताजनक है। जनगणना 2011 के अनुसार, "झारखंड में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 48.1 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत से काफी कम है।"[2] वहीं गोड्डा ज़िले में यह स्थिति और भी खराब है, "जहाँ आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर 40 प्रतिशत से भी कम आंकी गई है और बहुत ही कम महिलाएं माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच पाती है।"[3] यह आँकड़े शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी विषमता को दर्शाता है और स्थानीय व सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शोध की आवश्यकता को इंगित करता है। मानवशास्त्री जैसे हर्सकोविट्स (1955) और क्षत्रिय (2005) ने ज़ोर देकर कहा है कि "शैक्षणिक संस्थानों को स्थानीय सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप ढलना चाहिए, न कि स्वदेशी समुदायों से मानकीकृत शिक्षा मॉडल को अपनाने की अपेक्षा करनी चाहिए।"[4]

अध्ययन हेतु संथाल, पहाड़िया और उरांव समुदायों की 50 आदिवासी महिलाओं को नमूने के रूप में चुना गया है। गोड्डा जिला का चयन समग्र के रूप में किया गया है, क्योंकि यहाँ आदिवासी जनसंख्या अधिक है, मानव विकास सूचकांक (HDI) कम है और इस मुद्दे पर अब तक गहराई से कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

---

[1] Bernard, H. R. (2006). Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. AltaMira Press. p. 249.
[2] Ministry of Tribal Affairs. (2022). Annual Report 2021–22. Government of India. p. 13.
[3] Planning Commission. (2011). Report of the Working Group on Empowerment of Scheduled Tribes for the Twelfth Five-Year Plan. Government of India. p. 31.
[4] Herskovits, M. J. (1955). Cultural Anthropology. New York: Knopf. p. 89.

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

निदर्श के चयन में सुंदरपहाड़ी से 20 उत्तरदाता (जिसमें दूरस्थ टोले शामिल हैं) बोआरीजोर से 15 उत्तरदाता, पथरगामा से 15 उत्तरदाता का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 10 प्रमुख सूचनादाताओं जैसे– विद्यालय शिक्षक, आशा कार्यकर्ता एवं पंचायत प्रतिनिधि से भी साक्षात्कार किया गया, ताकि समुदाय के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।

आँकड़ा संग्रहण के उपकरण (Tools of Data Collection)

सशक्त और त्रिकोणीय (Triangulated) समझ सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया है :

1. संरचित साक्षात्कार अनुसूची– उत्तरदाताओं से जनसांख्यिकीय विवरण, शैक्षिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और सरकारी योजनाओं की जानकारी एकत्रित करने हेतु प्रश्नों को स्थानीय बोलियों (जैसे संथाली और पहाड़िया) में अनुवाद कर उत्तर प्राप्त किया गया है।
2. केंद्रित समूह चर्चा (FGDs)– 18–35 वर्ष की महिलाओं के साथ आयोजित, जिसमें बालिका शिक्षा, सांस्कृतिक वंचनाएँ, सुरक्षा चिंताएँ और आकांक्षाओं पर चर्चा हुई।
3. सहभागी अवलोकन (Participant Observation)– शोधकर्ता द्वारा दैनिक जीवन, विद्यालय जाने की आदतें, लैंगिक कार्य विभाजन एवं सामुदायिक बैठकों में भागीदारी को देखा गया ताकि सांस्कृतिक व्यवहारों की बेहतर जानकारी प्राप्त हो।

आंकड़ों का विश्लेषण (Data Analysis)

- ❖ संरचित साक्षात्कार से प्राप्त परिमाणात्मक आँकड़ा को MS Excel में टेबुलेट किया गया और आवृत्ति वितरण, प्रतिशत, तथा क्रॉस–टैबुलेशन के माध्यम से शैक्षिक सातत्य की पहचान की गई।
- ❖ गुणात्मक आँकड़े, जो FGDs और साक्षात्कार से प्राप्त हुआ, को थेमैटिक कोडिंग के माध्यम से विश्लेषित किया गया है। प्रमुख अवधारणाएँ जैसे 'विद्यालय अवसंरचना की कमी', 'बाल विवाह का दबाव' और 'सांस्कृतिक हानि का भय' को विषयगत श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। "इन निष्कर्षों की व्याख्या मानवशास्त्रीय सिद्धांतों जैसे कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद, लैंगिक पहुँच और संरचनात्मक वंचना के संदर्भ में की गई।"[5]

शोध संबंधी नैतिक विचार (Ethical Considerations)

उत्तरदाताओं को अनुसंधान के उद्देश्यों की जानकारी दी गई और उनकी भागीदारी पूर्णतः स्वैच्छिक रही है। साक्षात्कार आरंभ करने से पूर्व मौखिक सहमति प्राप्त की गई। प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखने हेतु उनके नामों का उपयोग नहीं करते हुए काल्पनिक नामों (Pseudonyms) का प्रयोग किया गया है। संवेदनशील जनसंख्या समूह होने के कारण महिलाओं के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया गया है।

सीमाएँ (Limitations)

सउद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के कारण गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है, यह भारत के सभी आदिवासी समुदायों पर निष्कर्ष लागू करने की सामान्यीकरण क्षमता को सीमित कर सकता है। साथ ही, भाषाई अवरोधों के कारण कभी–कभी स्थानीय अनुवादकों का सहयोग भी लिया गया है। त्रिकोणीय पद्धति (Method Triangulation) के प्रयोग से असमानताओं को काफी हद तक संतुलित भी किया गया है।

उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय रूपरेखा (Demographic Profile of Respondents)

गोड्डा ज़िले की आदिवासी महिलाओं को होने वाली शैक्षिक चुनौतियों को संदर्भित रूप में समझने के लिए उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में सम्मिलित 50 उत्तरदाताओं की आयु वितरण, जनजातीय पहचान, वैवाहिक स्थिति, परिवार का आकार, आर्थिक पृष्ठभूमि तथा माता–पिता की शिक्षा का विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया है।

आयु वितरण (Age Distribution)

उत्तरदाताओं को तीन प्रमुख आयु वर्गों 15–20 वर्ष, 21–30 वर्ष और 31–40 वर्ष में वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार के वर्गीकरण से विभिन्न पीढ़ियों में शैक्षिक पहुँच और आकांक्षाओं के बीच अंतर को समझना संभव हुआ है। तालिका संख्या–01 में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाता 21–30 और 31–40 आयु वर्ग से है, जो यह दर्शाता है कि युवा और मध्यम आयु वर्ग की आदिवासी महिलाएँ इस अध्ययन में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व की है।

आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
15–20	10	20 प्रतिशत
21–30	18	36 प्रतिशत
31–40	22	44 प्रतिशत
कुल	50	100 प्रतिशत

स्रोतः फील्ड सर्वेक्षण, 2025

[5] Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. Basic Books. pp. 5–26., Mohanty, A. K. (2009). Multilingual Education for Social Justice: Globalising the Local. Orient Blackswan. pp. 55–67.

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

उपर्युक्त वितरण के अनुसार शैक्षिक अनुभव आयु के अनुसार काफी भिन्न है। सबसे युवा वर्ग (15–20 वर्ष) में नामांकन दर अधिक है, परंतु घरेलू दायित्वों के चलते पढ़ाई छोड़ने की घटनाएँ भी सामने आई है।

जनजातीय संरचना (Tribal Composition)

अध्ययन में गोड्डा ज़िले की तीन प्रमुख जनजातियों की महिलाओं को शामिल किया गया है:

- ✓ संथाल– झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, जिनका जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है और जिनकी सांस्कृतिक पहचान अत्यंत सशक्त है।
- ✓ पहाड़िया– एक विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG), जो पहाड़ी वनों में रहते हैं और जिनकी साक्षरता दर अत्यंत निम्न है।
- ✓ उरांव– कृषक समुदाय, जिनमें शहरी प्रभाव धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

जनजाति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
संथाल	25	50 प्रतिशत
पहाड़िया	15	30 प्रतिशत
उरांव	20	20 प्रतिशत
कुल	50	100 प्रतिशत

स्रोतः फील्ड सर्वेक्षण, 2025

संथाल समुदाय की अधिक संख्या पथरगामा और बोआरीजोर प्रखंडों में जनसांख्यिकीय प्रभुत्व को दर्शाती है वहीं, पहाड़िया महिलाओं की सहभागिता अध्ययन में सबसे वंचित समुदायों के अनुभवों को उजागर करती है।

वैवाहिक स्थिति (Marital Status)

वैवाहिक स्थिति, विशेषकर कम उम्र में विवाह, आदिवासी महिलाओं में शैक्षिक विघटन का प्रमुख कारण है। 50 उत्तरदाताओं में 35 महिलाएँ (70 प्रतिशत) विवाहित, वहीं 15 महिलाएँ (30 प्रतिशत) अविवाहित है। विशेष रूप से पहाड़िया समुदाय में बाल विवाह के मामले अधिक है। 21–30 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं ने प्रायः अफसोस जताया कि पारिवारिक और बाल–बच्चों के पालन–पोषण की जिम्मेदारियों के कारण वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकीं।

आर्थिक पृष्ठभूमि (Economic Background)

आय स्तर शैक्षिक पहुँच का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अधिकांश उत्तरदाता आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कृषि, दैनिक मजदूरी या वन उत्पादों के संग्रहण जैसे अस्थायी स्रोतों पर निर्भर रहती है। केवल 8(16 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे परिवारों से हैं, जिनमें कोई व्यक्ति औपचारिक रोजगार (जैसे शिक्षक या पंचायत लिपिक) में कार्यरत है। किसी भी परिवार की मासिक आय ₹10,000 से अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त, 78 प्रतिशत परिवारों के पास स्मार्टफोन या डिजिटल उपकरण नहीं है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल साक्षरता की पहुँच सीमित है।

माता–पिता की शिक्षा (Parental Education)

विशेष रूप से माताओं का शिक्षा का स्तर अत्यंत चिंताजनक है। पिता की साक्षरता 38 प्रतिशत वहीं माता की केवल 12 प्रतिशत है। पिता, प्राथमिक से ज्यादा 16 प्रतिशत शिक्षित हैं जबकि माता, प्राथमिक से ज्यादा 4 प्रतिशत शिक्षित है। इस प्रकार के पीढ़ीगत शैक्षिक घाटा विशेषकर बालिकाओं में अशिक्षा के चक्र को बनाए रखने में सहायक होता है, क्योंकि वे अपनी माताओं के जीवन अनुभवों को अपने लिए आदर्श मानती है।

परिवार का आकार और निर्भरता (Family Size and Dependency)

प्रत्येक उत्तरदाता के परिवार में औसतन 6 से 8 सदस्य हैं, जिनमें कई आर्थिक रूप से आश्रित है। उच्च निर्भरता अनुपात के कारण कई लड़कियों को या तो घरेलू कार्यों में हाथ बँटाना पड़ा या मजदूरी करनी पड़ी, जिससे उनकी शिक्षा बाधित हुई।

शैक्षिक उपलब्धि के स्तर (Educational Attainment Levels)

गोड्डा ज़िले की आदिवासी महिलाओं में शैक्षिक उपलब्धि का स्तर न केवल ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहने का संकेत देता है, बल्कि यह विकासात्मक हस्तक्षेपों की वर्तमान प्रभावशीलता का भी एक महत्वपूर्ण सूचक है। 50 आदिवासी महिलाओं से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के स्तर को दर्शाया गया है। इन निष्कर्षों को शिक्षा पर नृवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक निरंतरता और संरचनात्मक विषमता के संदर्भ में भी विवेचित किया गया है।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

प्राप्त शैक्षिक स्तर

उत्तरदाताओं को उनके द्वारा पूर्ण की गई उच्चतम औपचारिक शिक्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वितरण तालिका संख्या–02 में दर्शाया गया है :

शिक्षा स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	20	40 प्रतिशत
प्राथमिक (कक्षा I–V)	15	30 प्रतिशत
माध्यमिक (कक्षा VI–XII)	10	20 प्रतिशत
स्नातक एवं उससे ऊपर	5	10 प्रतिशत
कुल	50	100 प्रतिशत

स्रोतः अध्ययन क्षेत्र सर्वेक्षण, 2025

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत महिलाएँ पूर्णतः निरक्षर है अर्थात् उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा के लिए नामांकन नहीं लिया या प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। केवल 10 प्रतिशत महिलाएँ स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर सकी है।

ग्राफः गोड्डा ज़िले की आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

ग्राफ के माध्यम से शैक्षिक वितरण को चित्रित किया गया हैः

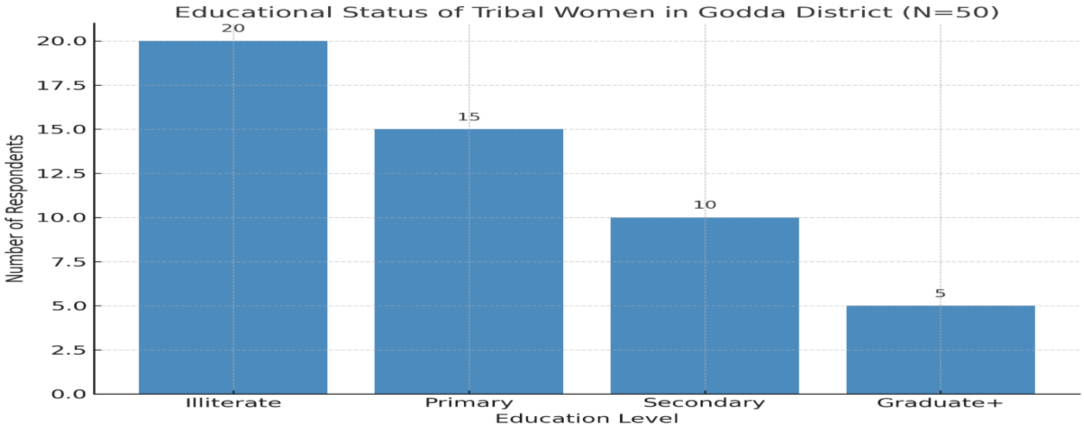

आंकड़ों की व्याख्या (Interpretation of Data)

अधिकांश महिलाओं का निरक्षर या केवल प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना, दीर्घकालिक शैक्षिक उपेक्षा को दर्शाता है। अध्ययन क्षेत्र अवलोकनों और चर्चाओं से निम्नलिखित प्रमुख कारण उभरकर सामने आया है।

सांस्कृतिक असंबद्धताः विशेषतः संथाल और पहाड़िया समुदायों में, शिक्षा को स्थानीय जीवन से असंबंधित और दूरस्थ समझा जाता है, क्योंकि वहाँ का ज्ञान परंपरागत रूप से मौखिक और अनुभवजन्य है।

आर्थिक दबावः कई महिलाओं ने कम उम्र में ही कृषि या घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ दिया, क्योंकि परिवार की प्राथमिकता तात्कालिक आर्थिक आवश्यकता होती है, न कि दीर्घकालिक शिक्षा निवेश।

लिंग आधारित मान्यताएँः कुछ परिवारों का मानना है कि 'लड़कियों की शिक्षा व्यर्थ है', क्योंकि उन्हें विवाह करके घर संभालना है।

उपर्युक्त निष्कर्ष नृविज्ञानी वेरीयर एल्विन (1959) के कार्यों से मेल खाता है, जिनका मानना था कि "आदिवासी समूहों में औपचारिक शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती है, जब तक वह स्थानीय संस्कृति, भाषा और मूल्यों का सम्मान न करे।"[6]

पीढ़ीगत अंतर (Inter-Generational Differences)

15–20 वर्ष की उत्तरदाताओं की तुलना में पुराने आयु वर्ग की महिलाओं का शैक्षिक स्तर थोड़ा बेहतर था। इस आयु वर्ग में माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकन अपेक्षाकृत अधिक था। कक्षा VI से X के बीच ड्रॉपआउट दर अब भी अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं ने प्राथमिक स्तर पर कुछ सफलता पाई है, परंतु माध्यमिक शिक्षा में अब भी बड़ी खाई बनी हुई है।

---

[6] Elwin, V. (1959). A Philosophy for NEFA. Shillong: North East Frontier Agency. p. 102.

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

जनजातीय भिन्नता (Tribal Variation)

तीनों जनजातीय समूहों के बीच उरांव समुदाय की महिलाओं ने सर्वाधिक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें 10 में से 3 महिलाएँ स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की थी, संथाल महिलाएँ मुख्यतः प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रही है, पहाड़िया समुदाय की महिलाएँ सबसे अधिक पिछड़े स्तर पर थी जिसमें 15 में से 12 महिलाएँ निरक्षर थी। इस प्रकार की भिन्नता दर्शाती है कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) जैसे पहाड़िया समुदायों को विशेष रूप से लक्षित शैक्षिक और संरचनात्मक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

शिक्षा में सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ (Socio & Cultural Barriers to Education)

गोड्डा ज़िले की आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार की राह में सबसे जटिल और स्थायी चुनौती है–सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं की गहरी जड़ें, जो समुदाय के मूल्य–तंत्र, परंपराओं, पारिवारिक संरचना और लिंग आधारित भूमिकाओं से संचालित होती है। नृवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बाधाएँ केवल 'पिछड़ेपन' की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसे सांस्कृतिक तंत्र का हिस्सा है, जो आदिवासी समाजों में अर्थ, सामाजिक व्यवस्था और पहचान को बनाए रखता है।

पारंपरिक दृष्टिकोण और शिक्षा (Traditional Worldviews and Education)

संथाल, पहाड़िया और उरांव जैसे समुदायों की सांस्कृतिक दृष्टि एनीमिज़्म, मौखिक इतिहास और सामूहिक अनुष्ठानों पर आधारित होती है। इन समुदायों में शिक्षा परंपरागत रूप से अनौपचारिक प्रशिक्षुता (Apprenticeship) के रूप में होती है, जिसमें ज्ञान कहानियों, कृषि कार्यों और अनुष्ठानिक सहभागिता के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। "औपचारिक शिक्षा, जिसमें लिखित पाठ्यपुस्तकें, अनुशासन, परीक्षा और अमूर्त अवधारणाओं पर ज़ोर होता है, आदिवासी अभिभावकों और विद्यार्थियों को अनोखा और अप्रासंगिक प्रतीत होता है।"[7]

लिंग आधारित भूमिकाएँ और पितृसत्तात्मक मानदंड (Gender Roles and Patriarchal Norms)

आदिवासी समाजों में लिंग समानता अपेक्षाकृत अधिक है, पर व्यवहार में यह स्थिति भ्रामक सिद्ध होती है। गोड्डा क्षेत्र में लड़कियों पर घरेलू कार्यों, छोटे भाई–बहनों की देखभाल और खेतों में श्रम का अत्यधिक दबाव होता है। यह श्रम अपेक्षा 8–9 वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाती है और किशोरावस्था तक जारी रहती है। 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे विद्यालय से अनुपस्थित रहती थी क्योंकि उन्हें घरेलू काम करने होते थे। 68 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने विद्यालय छोड़ा क्योंकि परिवार उन्हें 'गैर–ज़रूरी' कार्यों (जैसे विद्यालय जाना) के लिए नहीं छोड़ सकते थे।

सामुदायिक मानदंड और सामाजिक दबाव (Community Norms and Peer Pressure)

नृवंशवैज्ञानिक अवलोकनों के दौरान सामुदायिक अपेक्षाएँ और सामाजिक निगरानी के रूप में एक महत्वपूर्ण बाधा सामने आई। छोटे और सघन आदिवासी गांवों में सामुदायिक मानदंडों से विचलन को अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसी लड़कियाँ जो गाँव की सीमा से बाहर विद्यालय जाती है, उन्हें चर्चा या नैतिक संदेह का सामना करना पड़ता है। परिवारों को डर रहता है कि 'बहुत ज्यादा पढ़ाई' करने वाली बेटियाँ आदिवासी विवाह योग्यताओं से बाहर हो जाएगी। एक संथाल महिला (पथरगामा से) ने बताया, "पड़ोसी कहते थे कि अगर मेरी बेटी कक्षा VIII के बाद भी विद्यालय गई, तो वह भाग जाएगी। कोई अच्छा आदिवासी लड़का उसे नहीं अपनाएगा।"

धर्म और अनुष्ठानिक बाध्यताएँ (Religion and Ritual Obligations)

गोड्डा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में ऋतुकालीन त्यौहार और अनुष्ठान विद्यालय उपस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाता है। सोहराय, सरहुल और बाहा जैसे प्रमुख त्योहार कई दिनों तक चलता है और इनमें महिलाओं व लड़कियों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इस कारण इन अवधियों में विद्यालय पूरी तरह खाली रहता है और लगातार अनुपस्थिति से ड्रॉपआउट की स्थिति उत्पन्न होती है। बोआरिजोर के शिक्षकों ने अपनी चिंता व्यक्त की कि छात्राएँ इन अनुष्ठानों के कारण लंबे समय तक अनुपस्थित रहती है और स्कूलों में ऐसा कोई सांस्कृतिक रूप से संरेखित कैलेंडर नहीं है, जो इन त्योहारों को ध्यान में रखे।

आर्थिक और अवसंरचनात्मक बाधाएँ (Economic and Infrastructure Constraints)

गोड्डा जिले की आदिवासी महिलाओं की शिक्षा–यात्रा स्थायी घरेलू गरीबी और कमज़ोर सार्वजनिक अवसंरचना जैसी दोहरी समस्या से ग्रस्त है। कई बार परिवारों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच होती है, लेकिन यह सोच अस्थिर आय, मौसमी प्रवासन और स्थानीय विद्यालयों में तथा उनके मार्ग में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण व्यवहार नहीं बदल पाती है।
हाल के UDISE (झारखंड) आंकड़ों के अनुसार, "माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन दर (Gross Enrolment Ratio) 89.5 प्रतिशत तक पहुँचती है, परंतु आठवीं कक्षा के बाद लड़कियों का नामांकन तेज़ी से घटा है। यह गिरावट घरेलू आय और विद्यालय स्तर की सुविधाओं से स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है।"[8]

घरेलू गरीबी और 'अवसर लागत' की दुविधा (Household Poverty and the 'Opportunity&Cost' Dilemm)

क्षेत्रीय अध्ययन में पाया गया कि 50 में से 42 उत्तरदाता (84 प्रतिशत) ऐसे परिवारों से थी, जो जीविका हेतु कृषि, दैनिक मजदूरी या वन उत्पादों के संग्रह पर निर्भर थे। जिस माह में कृषि कार्य में व्यस्तता कम जैसे (जुलाई–सितंबर और

---

[7] Xaxa, V. (2005). Politics of Language, Religion and Identity: Tribes in India. Economic and Political Weekly, 40(13), 1363–1370.

[8] Ministry of Tribal Affairs. (2023). Annual Report 2022–23. Government of India. pp. 10–14.

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

जनवरी–फरवरी) में किशोरी लड़कियाँ ईंट भट्ठों या अभ्रक खनन स्थलों पर मजदूरी करती है, जिससे उन्हें ₹120–₹150 प्रतिदिन की आमदनी होती है, यह राशि उनके परिवारों के लिए छोड़ना संभव नहीं होता है। जब एक 17 वर्षीय संथाल लड़की से पूछा गया कि उसने छठी कक्षा के बाद विद्यालय क्यों छोड़ा, तो उसने जवाब दिया, "मेरे विद्यालय जाने से घर का एक–एक रुपया रुक जाता है।"

संसाधनविहीन विद्यालय अवसंरचना (Under-resourced School Infrastructure)
स्वतंत्र विद्यालय सूचना पोर्टल पर किए गए निरीक्षण के अनुसार विद्यालय की स्थितिः–

- गाँव में रहने वाली लड़कियों को विद्यालयों की खराब भौतिक स्थिति उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई छोड़ने के लिए प्रेरित करती है।
- सरकारी उच्च विद्यालय सरोटिया (UDISE)– बिजली, चारदीवारी एवं पुस्तकालय की कमी।
- सरकारी उच्च विद्यालय देवबांधा– बिजली की सुविधा नहीं, सिर्फ लड़कों के लिए एक शौचालय, लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं।
- उन्नत प्राथमिक विद्यालय घाटियारी– सात कमरे पर सिर्फ एक लड़कियों का शौचालय और अस्थायी जल आपूर्ति।

किशोरी लड़कियों के लिए स्वतंत्र और कार्यशील शौचालयों की अनुपलब्धता मात्र असुविधा नहीं है, विशेष रूप से मासिक धर्म के समय विद्यालय छोड़ने का एक निर्णायक कारण बन जाती है। 2024 में जारी राष्ट्रीय आँकड़ा के अनुसार, "झारखंड में अभी भी सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए 80 प्रतिशत से भी कम शौचालय है और गोड्डा जैसे आदिवासी–बहुल जिले राज्य के औसत से भी पीछे है।"[9]

बिजली, कनेक्टिविटी और डिजिटल विभाजन (Electricity, Connectivity and the Digital Divide)

कोविड के बाद की शिक्षा पद्धति डिजिटल या मिश्रित विधि पर संचालित होती है, लेकिन सुदुरवर्ती गांवों में बिजली आपूर्ति अब भी अनियमित और सीमित है। सरकारी डैशबोर्ड पर कई विद्यालय स्थापना के दशकों बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। भारतनेट परियोजना (Phase II) को ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए क्रांतिकारी योजना माना जाता था, परंतु यह अभी तक अध्ययन किए गए 9 गांवों में से केवल 2 तक ही इसकी पहुंच है। कुल चयनित 50 उत्तरदात्रियों में से सिर्फ एक परिवार के पास इंटरनेट सक्षम उपकरण है।

दूरी और परिवहन की चुनौतियाँ (Distance and Transportation Risks)

पांच गांवों की उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें 3–5 किमी जंगली रास्तों से चलकर माध्यमिक विद्यालय जाना होता है; जबकि माध्यमिक विद्यालय ब्लॉक मुख्यालय में स्थित है, जो विद्यालय विलय नीति के कारण और भी दूर हुए हैं। अभिभावकों ने अपनी बेटियों को जंगल के जानवरों, नशे में धुत खनिकों और मानसून की नदियों से होने वाले ख़तरों के कारण किशोरावस्था में विद्यालय जाना बंद करवा दिया है। समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन भत्ता का प्रावधान तो है, पर स्थानीय पंचायत अभिलेख से स्पष्ट है कि वितरण बेहद अनियमित है। नीति आयोग द्वारा चयनित जिलों के प्रतिवेदन में "अंतिम–चरण की विफलताओं पर चिंता व्यक्त की गई है, धनराशि तो है, पर निगरानी और सामुदायिक फीडबैक तंत्र कमज़ोर है।"[10]

भाषा और पाठ्यचर्या से जुड़ी समस्याएँ (Language and Curriculum Issues)

भाषा केवल ज्ञान संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदायों के लिए यह संस्कृति, पहचान और जीवन–दृष्टि का प्रमुख संवाहक होती है। भारत की औपचारिक शिक्षा प्रणाली ने ऐतिहासिक रूप से हिंदी और अंग्रेज़ी जैसी प्रभावशाली भाषाओं को प्राथमिकता दी है, जिससे संथाली, पहाड़िया और कुरुख जैसी आदिवासी भाषाएँ हाशिए पर चली गई है। इस प्रकार की भाषाई असंगति आदिवासी छात्रों के लिए विशेष रूप से लड़कियों के लिए, जो विद्यालय में प्रवेश से पहले औपचारिक भाषा–शिक्षा के कम अवसर पाती है, अधिगम के मार्ग में मौलिक बाधा बन जाती है।

मातृभाषा और संज्ञानात्मक विकास (Mother Tongue and Cognitive Development)

यूनेस्को (2003) और अन्य शैक्षिक शोध संस्थाओं ने बार–बार इस बात पर बल दिया है कि "मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (MTB-MLE), विशेष रूप से बहुभाषी समाजों में, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।"[11] गोड्डा में सरकारी विद्यालयों में शिक्षण की प्रमुख भाषा हिंदी है, भले ही कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग संथाली या पहाड़िया को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। पथरगामा और बोरियोर में किए गए साक्षात्कारों में कई आदिवासी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने विद्यालय इसलिए छोड़ा क्योंकि वे "शिक्षक की बात समझ नहीं पाती थी" या "हिंदी में पढ़ने को कहा जाता था तो डर लगता था।" इन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि भाषा विद्यालय प्रणाली में प्रवेश की 'चौकीदार' की भूमिका निभाती है, जो कई विद्यार्थियों को प्रवेश करने से पूर्व दरवाज़े पर ही रोक देती है।

---

[9] Ministry of Tribal Affairs. (2023). Annual Report 2022–23. Government of India. pp. 10–14.
[10] NITI Aayog. (2021). Aspirational Districts Programme Evaluation Report. Government of India. pp. 28–32.
[11] UNESCO. (2003). Education in a Multilingual World. Education Position Paper. pp. 9–14.

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

पाठ्यचर्या की सामग्री और सांस्कृतिक अलगाव (Curriculum Content and Cultural Alienation)

भाषा से भी आगे, विद्यालय की पाठ्यचर्या स्वयं भी सांस्कृतिक रूप से अपरिचित होती है। पाठ्यपुस्तकों में आदिवासी इतिहास, लोककथाएं, स्थानीय नायक या कृषि ज्ञान की कमी है। इसमें ज़ोर ऐसे मानकीकृत विषयों पर होता है, जो अधिकतर शहरी या सवर्ण हिंदू जीवन से मेल खाता है, जबकि आदिवासी जीवनानुभवों से उनका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। नेतृत्त्वशास्त्री पाउलो फ्रेरे (1970) ने इस प्रकार की शिक्षा को 'बैंकिंग मॉडल' कहा है, जहाँ विद्यार्थियों "बिना उनकी अपनी ज्ञान प्रणालियों को मान्यता दिए निष्क्रिय पात्र मानकर उनमें ज्ञान 'संग्रह' कर दिया जाता है।"[12]

आदिवासी शिक्षक और भाषा संसाधनों की कमी (Lack of Tribal Teachers and Language Resources)

प्रशिक्षित आदिवासी शिक्षकों की भारी कमी इस भाषाई अंतर को और गहरा बनाता है, जो विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ाने में अक्षम थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश की गई है, लेकिन गोड्डा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन बेहद कमज़ोर है। इसके अलावा, संथाली और पहाड़िया भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री विशेष रूप से माध्यमिक और सेकेंडरी स्तर भी बेहद कम है। झारखंड सरकार ने ओल चिकी लिपि में कुछ संथाली पाठ्यपुस्तकों की शुरुआत की है, परंतु इसका वितरण असमान है और अधिकांश शिक्षक इसका प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं हैं।

शिक्षा का लिंग आधारित अनुभव (Gendered Experience of Education)

गोड्डा की आदिवासी लड़कियों की शैक्षिक यात्रा केवल उनके अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य होने से निर्धारित नहीं होती है, यह उनकी लैंगिक सामाजिक स्थिति से भी गहराई से प्रभावित होती है, जो आदिवासी परिवारों और समुदायों में उनकी भूमिका को परिभाषित करती है। आदिवासी समाजों को प्रायः सवर्ण हिंदू मानदंडों की तुलना में अधिक समतावादी माना जाता है, फिर भी गोड्डा में किए गए क्षेत्रीय अध्ययन में स्पष्ट रूप से आदिवासी लड़कियाँ शिक्षा की तुलना में घरेलूता (Domesticity) को बढ़ावा देने वाली लिंग–विशिष्ट अपेक्षाओं, वर्जनाओं और भूमिकाओं के कारण वंचित होती है।

घरेलू जिम्मेदारियाँ और समय का अभाव (Domestic Responsibilities and Time Poverty)

साक्षात्कारों और समूह चर्चाओं से स्पष्ट हुआ है कि घरेलू कार्यों का बोझ असमानुपतिक रूप से लड़कियों के शिक्षा पर पड़ता है। बहुत छोटी उम्र 8 वर्ष की आयु से ही आदिवासी लड़कियों को खाना बनाना, पानी लाना, पशुओं की देखभाल करना और छोटे भाई–बहनों की जिम्मेदारी उठाना सिखाया जाता है। इसके विपरीत, लड़कों को, संसाधनों की कमी के बावजूद, अधिक जागरूकता के साथ विद्यालय भेजा जाता है। 50 आदिवासी महिलाओं में से 76 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने घरेलू जिम्मेदारियों के कारण विद्यालय छोड़ दिया है। 58 प्रतिशत प्रमुख कृषि सीज़न में प्रति माह 10 से अधिक दिन विद्यालय से अनुपस्थित रहती है।

शिक्षा और विवाह योग्यता (Education and Marriageability)

महिलाओं ने बताया कि रूढ़िवादी या अलग–थलग आदिवासी समूहों में लड़कियों की उच्च शिक्षा को विवाह में बाधा के रूप में देखा जाता है। शिक्षित लड़कियों को अधिक आज़ाद ख्यालों वाली, दहेज में महंगी या अन्य जाति/जनजाति के लड़कों से विवाह की इच्छुक माना जाता है, जो पारंपरिक वैवाहिक बंधनों को बाधित करता है। 19 वर्षीय संथाल लड़की, जो इंटरमीडिएट पास थी के अनुसार, "मेरे रिश्तेदारों ने पिताजी को चेतावनी देते हुए कहा, अगर मैं कॉलेज जाऊँगी तो किसी शहर के लड़के के साथ भाग जाऊँगी।" वह नर्स बनना चाहती थी, परंतु सामुदायिक दबाव के कारण उसकी जल्दी शादी करवा दी गई।

सरकारी पहल और उनकी सीमाएँ (Government Initiatives and Gaps)

पिछले दो दशकों में भारत सरकार और झारखंड सरकार ने आदिवासी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये हैं, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV), अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ, डिजिटल इंडिया योजनाएँ और आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम शामिल है, जिसमें गोड्डा जिला शामिल है। इन पहलों के माध्यम से कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। क्षेत्रीय अध्ययन से स्पष्ट है कि कार्यान्वयन, सूचना संप्रेषण और स्थानीय भागीदारी की कमी के कारण इन योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव काफी हद तक कमज़ोर हो गया है।

मौजूदा योजनाएँ (Existing Schemes)

निःशुल्क सर्व शिक्षा अभियान (SSA) एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (RTE) कक्षा आठवीं तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इससे आदिवासी लड़कियों के प्राथमिक स्तर पर नामांकन में सुधार हुआ है।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)– इस योजना के अंतर्गत वंचित वर्ग की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने के लिए शुरू किया गया था। गोड्डा जिले के अधिकांश प्रखंडों में KGBV कार्यरत है।
- प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ ST छात्रों की स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चों को कवर करने का प्रयास किया गया है।

[12] Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum. pp. 72–78.

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

- साइकिल योजनाएँ और यूनिफॉर्म अनुदान जैसी पहलें आदिवासी लड़कियों की गतिशीलता और गरिमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत, गोड्डा जैसे आकांक्षी जिलों के स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम और ई–कंटेंट डिलीवरी के लिए प्राथमिकता दी गई है।

सुझाव और नीतिगत अनुशंसाएँ (Suggestions and Policy Recommendations)

गोड्डा जिले की शैक्षिक प्रणाली में देखे गए नृविज्ञान संबंधी अंतर्दृष्टियों, अध्ययन क्षेत्र आँकड़ा और संरचनात्मक अंतरालों के आधार पर, इस अनुभाग में आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार हेतु कुछ ठोस अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई है। ये सुझाव केवल भौतिक ढाँचागत सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, भाषाई और लैंगिक अवरोधों को ध्यान में रखते हुए समग्र और समुदाय–केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने की वकालत करता है।

- मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (MTB&MLE) को बढ़ावा देना।
- विद्यालय अवसंरचना को सुदृढ़ करना और स्थानीयकृत बनाना।
- आदिवासी महिला शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से आर्थिक बाधाओं का समाधान।
- लैंगिक–संवेदनशील हस्तक्षेप।
- सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ावा देना।
- पारदर्शी निगरानी प्रणाली और जवाबदेही।

निष्कर्ष

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा सुधार केवल थोपे गए सरकारी प्रयासों से नहीं हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि:

- जो भी नीतियाँ निर्मित हो, नृविज्ञान की समझ पर आधारित होने चाहिए।
- स्थानीय लोगों को सशक्त बनाया जाए।
- संस्थागत संस्कृति में भी बदलाव लाया जाए।

शिक्षा से जुड़ी नीतियाँ आदिवासी समुदायों विशेषकर महिलाओं के साथ मिलकर सह–निर्मित (Co-Designed) होनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे अच्छी तरह समझती है कि उनके संदर्भ में उचित है भी या नहीं। गोड्डा जिले में आदिवासी महिलाओं की शिक्षा की स्थिति जटिल और स्थायी संरचनात्मक वंचना, सांस्कृतिक असंगति और लैंगिक बहिष्करण की मजबूत परतों को उजागर करती है। सरकार द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को लेकर बढ़ती जागरूकता के बावजूद, संथाल और पहाड़िया जैसी जनजातियों से आने वाली महिलाएँ आज भी भारत की सबसे अधिक शैक्षिक रूप से उपेक्षित आबादी में शामिल है। अध्ययन के अंतर्गत सांख्यिकीय विश्लेषण और नृविज्ञान संबंधी अध्ययन करते हुए बहुआयामी वंचना की एक गंभीर समझ प्रदान करता है। शैक्षिक बहिष्करण को केवल आर्थिक कारकों के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। गरीबी, पलायन और अवसर लागत जैसी बाधाएँ वास्तविक है, वहीं समान रूप से प्रभावशाली भी है। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के माध्यम से शिक्षा को देखा और अनुभव किया जाता है। भाषा एक प्रमुख बाधा बनी हुई है; जब शिक्षा हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यमों में दी जाती है और आदिवासी मातृभाषाओं की उपेक्षा होती है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं और सफल भी नहीं हो पाते हैं। इसी तरह, लैंगिक भूमिकाएँ, लड़कियों को शीघ्र विवाह, देखभाल के कार्यों या कृषि श्रम की ओर धकेलती है। इस प्रकार की धारणा से यह स्पष्ट होता है कि **"विद्यालय लड़कियों के लिए नहीं है।"**

संस्थागत ढाँचा भी इन बहुस्तरीय चुनौतियों को पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं कर पा रहा है। कई विद्यालयों में अभी भी बुनियादी सुविधायें विशेष रूप से दूर–दराज़ के गाँवों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय, बिजली या सुरक्षित परिवहन की कमी है। साथ ही, शिक्षकों में आदिवासी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति एक ऐसा वातावरण पैदा करती है, जहाँ छात्राएं अलग–थलग और अदृश्य महसूस करती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) और अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ केवल कागज़ों पर मौजूद है, पर क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान इन समुदायों के लिए संचालित योजनाओं में कार्यान्वयन में असंगति, कमज़ोर निगरानी और आदिवासी भाषाओं में सीमित प्रचार के चलते कई महिलाएँ, जो वास्तव में उनके लिए बनाए गए योजनाएँ हैं, उन लाभों से अनभिज्ञ हैं, देखने को मिला है। नृवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आदिवासी समाजों में, शिक्षा को केवल एक औपचारिक क्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामुदायिक मूल्यों, स्थानीय भाषाओं और सामूहिक जीवन की लय के साथ मेल खाता हो। आदिवासी ज्ञान प्रणाली, मौखिक परंपराएँ और सामूहिक अधिगम विधियाँ ऐसी मूल्यवान अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करती है, जिसे पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में समाहित किया जाना चाहिए।

राज्य की अपेक्षाओं और आदिवासी यथार्थों के बीच की खाई को पाटने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है :

- शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम निर्माण में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।
- प्रारंभिक कक्षाओं में स्थानीय भाषाओं को शिक्षण का मूल आधार बनाया जाए।
- विद्यालय प्रबंधन और सामुदायिक पहलों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- शिक्षा को मुख्यधारा में समाहित करने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि पहचान के तौर पर सशक्तिकरण के रूप में पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-7 | July - 2025

निष्कर्षतः, आगे का मार्ग केवल अधिक विद्यालयों या अधिक योजनाओं के निर्माण से नहीं निकलेगा, बल्कि शिक्षा की पूरी संरचना को जनजतीय दृष्टि से पुनर्संरचित करना होगा, जिससे वे वास्तव में लाभान्वित हो सके। गोड्डा की आदिवासी महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करना केवल निवेश और अवसंरचना का नहीं, बल्कि सहानुभूति, सम्मान और भागीदारी का भी प्रश्न है। नृविज्ञान के अनुसार वास्तविक परिवर्तन तब होता है, जब प्रणालियाँ लोगों के अनुसार खुद को ढालती है, न कि तब लोगों को प्रणालियों के अनुसार ढलने के लिए मजबूर किया जाता है। यही सत्य आदिवासी भारत में शैक्षिक सुधार के केंद्र में अपनाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ–सूची

1. Elwin, V. (1959). A Philosophy for NEFA. Shillong: North East Frontier Agency. p. 102.
2. Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum. pp. 72–78.
3. Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. Basic Books. pp. 5–26.
4. Herskovits, M. J. (1955). Cultural Anthropology. New York: Knopf. p. 89.
5. Ministry of Tribal Affairs. (2022). Annual Report 2021–22. Government of India. p. 13.
6. **Ministry of Tribal Affairs.** (2023). *Annual Report 2022–23*. Government of India. pp. 10–14.
7. Mohanty, A. K. (2009). Multilingual Education for Social Justice: Globalising the Local. Orient Blackswan. pp. 55–67.
8. NITI Aayog. (2021). Aspirational Districts Programme Evaluation Report. Government of India. pp. 28–32.
9. Planning Commission. (2011). Report of the Working Group on Empowerment of Scheduled Tribes for the Twelfth Five-Year Plan. Government of India. p. 31.
10. UNESCO. (2003). Education in a Multilingual World. Education Position Paper. pp. 9–14.
11. Xaxa, V. (2005). Politics of Language, Religion and Identity: Tribes in India. Economic and Political Weekly, 40(13), 1363–1370.